भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1702
गुरुवार, 5 दिसंबर, 2024/14 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

तेलंगाना में विमानपत्तन

1702. श्री अरविंद धर्मापुरी:

श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेलंगाना के लिए स्वीकृत/स्वीकृति के लिए लंबित विमानपत्तनों की स्वीकृति और निर्माण की समय-सीमा सहित वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पूरा हो चुका है और यदि हां, तो विशेष रूप से जक्रानपल्ली विमानपत्तन के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त विमानपत्तनों के विकास के लिए कितनी निधियां आवंटित और जारी की गई हैं;

(घ) नज़ामाबाद और आसपास के क्षेत्रों में विमानपत्तन के यात्री संख्या संबंधी अनुमान और अनुमानित आर्थिक प्रभाव संबंधी डेटा क्या है; और

(ङ) तेलंगाना में अनुमानित परिचालन समय-सीमा के साथ विद्यमान विमानपत्तनों के पुनरुद्धार की स्थिति क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले)

(क) से (ग) : भारत सरकार (जीओआई) ने देश में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास हेतु ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 तैयार की है। इस नीति के अनुसार, यदि राज्य सरकार सहित कोई भी हवाईअड्डा विकासकर्ता हवाईअड्डा विकसित करना चाहता है, तो उन्हें उपयुक्त स्थल को चिह्नित करना होगा और हवाईअड्डे के निर्माण हेतु व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन कराना होगा तथा 'साइट क्लियरेंस' व तत्पश्चात 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) ने पूर्व में तेलंगाना राज्य में हवाईअड्डों के विकास के लिए छह स्थलों का व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन किया था और 03 स्थलों अर्थात् वारंगल (ब्राउनफील्ड), आदिलाबाद (ब्राउनफील्ड) और जक्रानपल्ली (ग्रीनफील्ड) को तकनीकी रूप से व्यवहार्य पाया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने तेलंगाना सरकार को इन तीन हवाईअड्डों के विकास का कार्य आरंभ करने से पूर्व नया ऑबस्टिकल

लिमिटेडेशन सर्वेक्षण (ओएलएस) सर्वेक्षण करने और नागर विमानन मंत्रालय और अन्य विनियामक/सांविधिक प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करने की सलाह दी है।

राज्य सरकार ने अब नए हवाईअड्डों के विकास के लिए भद्राद्री-कोठागुडेम और एंथरागांव, पेड्डापल्ली में नए स्थलों को चिह्नित किया है।

तथापि, भारत सरकार को तेलंगाना राज्य में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए तेलंगाना सरकार या किसी हवाईअड्डा विकासकर्ता से जीएफए नीति के अंतर्गत 'साइट क्लीयरेंस' के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, जीएफए नीति के अनुसार, भूमि अधिग्रहण, आर एंड आर, वित्तपोषण, आदि सहित ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित हवाईअड्डा विकासकर्ता या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, की है। हवाईअड्डा परियोजनाओं के पूरा होने की समयसीमा कई कारकों जैसे भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य मंजूरी की उपलब्धता, वित्तीय समापन, आदि पर निर्भर करती है।

(घ) : हवाईअड्डे आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभरे हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था पर इनका गुणात्मक प्रभाव पड़ा है। नागर विमानन क्षेत्र और आर्थिक विकास के बीच संबंध सर्वविदित है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) का अध्ययन यह दर्शाता है कि हवाई सम्पर्क का आर्थिक गुणक 3.25 और रोजगार गुणक 6.1 है। इसके अलावा, राज्य में हवाईअड्डों के विकास से क्षेत्रीय संपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन तथा पर्यटन में वृद्धि होने की संभावना है।

(ङ) : नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 21-10-2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देना और आम जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाना है। आरसीएस-उड़ान योजना के अंतर्गत, असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों का जीर्णोद्धार/उन्नयन, वैध बोली के माध्यम से उन्हें चिह्नित करने और चयनित एयरलाइन प्रचालक को कार्य अवॉर्ड करने के पश्चात किया जाता है।

तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद, अलेरू और कागजपुर हवाईअड्डे/ हवाई पट्टियाँ, उड़ान योजना के दस्तावेज़ में असेवित हवाईअड्डों की अस्थायी सूची में उपलब्ध हैं। किसी भी एयरलाइन बोलीदाता ने आज तक आदिलाबाद, अलेरू और कागजपुर हवाई पट्टियों से आरसीएस उड़ान परिचालित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। यदि कोई एयरलाइन आरसीएस बोली के भविष्य के दौर में उपर्युक्त हवाई पट्टियों को जोड़ने वाले मार्गों के लिए आवेदन करती है, तो उस पर आरसीएस के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा।